

खबर संक्षेप

करंट की चपेट में आया लाइन हेल्पर, अस्पताल में मर्ती



सतना। नागौद क्षेत्र के हरदुआ में परमिट लेकर लाइन में कार्य कर रहे लाइन हेल्पर राकेश कुशवाहा करंट की चपेट में आने से घुरी तरह झुलसा गया जिसे सरकारी बल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि सबस्टेशन में पदस्थ ऑपरैटर की लापरवाही से अचानक बिजली चालू कर दी गई जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। वहीं मामले में विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि ऑपरैटर के रूप में यहां सचिन पदस्थ है पर सचिन और उसके पिता ब्रजेश पटेल दोनों कार्य करते हैं।

अतिरिक्त परिवहन अधिकारी ने की स्कूल बसों की जांच, फिटनेस निरस्त



सतना। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने मैहर जिले में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार स्कूल बसों की जांच की इस दौरान 41 बसों को चेक किया गया। जिसमें 01 बस एमपी 19 पी 0676 गुरुकुल एकेडमी स्कूल मैहर की बस सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नहीं पाई गई। इस बस की फिटनेस निरस्त की गई जबकि 03 बसों में आंशिक कमियां होने से 4000 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया। संस्था द्वारा उन कमियों को अति शीघ्र पूर्ण कर लेने को कहा गया है। साथ ही 01 बस सवारी गाड़ी जिसका रंग रोगन, ठीक न होने से बस क्रमांक एमपी 17पी 0419 की फिटनेस निरस्त की गई है। कुल कार्यवाही 03 बसों से 4000 रुपये राजस्व वसूला गया।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का पुनर्गठन सतना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार मैहर कलेक्टर रानी बाटड द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) का पुनर्गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार कलेक्टर मैहर को अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को उपाध्यक्ष तथा वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल सतना को सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, महाप्रबंधक परियोजना क्रियाव्ययन इकाई जल निगम सतना को सदस्य तथा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतना को सदस्य, सचिव नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने बताया कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के लिए प्रत्येक गांव का जायजा लेने के बाद ग्राम कार्य योजना तैयार करना। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने की दृष्टि से जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने का कार्य जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

जिले में अब तक 107.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज सतना। जिले में इस वर्ष 1 जून से 4 जुलाई 2024 तक 107.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 207.1 मि.मी., सोहावन (रघुराजनगर) में 99.4 मि.मी., बरौथा (मद्दगवां) में 60.9 मि.मी., बिरसिंहपुर में 91 मि.मी., रामपुर बाघेलाना में 49 मि.मी., नागौद में 138.3 मि.मी., जसो (नागौद) में 42 मि.मी. एवं उन्नेहरा में 175 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

सड़कों के मरम्मतिकरण में मनमानी, बाजार में रेस्टोरेशन बना मजाक... बगहा में कमिश्नर ने लगाई फटकार

सतना। सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क को पुनः ठीक करने के लिए रेस्टोरेशन की अपनानी गई प्रक्रिया संदेह के दायरे में है। लालता चौक, गांधी चौक, फूलचंद चौक समेत पूरे बाजार में रेस्टोरेशन मजाक बन गया है। मनमानी के कारण फिर से सड़क टूट गई है। इस बीच नगर निगम आयुक्त डॉ.शेर सिंह मीना अपने प्रातः भ्रमण के दौरान शहर में सीवर लाइन बिछाये जाने के उपरांत किये जा रहे रेस्टोरेशन कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोठी रोड में चल रहे रेस्टोरेशन का कार्य देखा। जब डॉ.मीना जेपी मोड़ बगहा के सामने निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्हें रेस्टोरेशन के कार्य में गड़बड़ी दिखाई दी। रेस्टोरेशन किये गये स्थान पर गड्ढे को देखकर नगर निगम आयुक्त ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कि जहां-जहां रेस्टोरेशन का कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है, उसे तत्काल ठीक कराया जाये। नगर निगम आयुक्त ने कहा है कि रेस्टोरेशन किये जाने के दौरान वर्षा के पानी की निकासी का विशेष ध्यान दिया जाये। वर्षा का जल रोड में न फैले बल्कि नाली की ओर जाना चाहिये। रेस्टोरेशन कराते समय जल की निकासी की व्यवस्था इस दंग से की जाये कि वर्षा के जल का भराव न हो। आयुक्त ने बहुत नगर



में किये गये कार्य का निरीक्षण किया। रीवा रोड में निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां-जहां सीवर लाइन का मेन होल है, उसके पास आवागमन में गड़बे न रहें। रेस्टोरेशन को तीव्र गति से कराया जाये। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार को कोठी रोड, सिटी कोतवाली रोड, टिकुरिया टोला, वार्ड क्र.10 भरत नगर, अनुपमा स्कूल एवं वृन्दावन पार्क के पास रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है।

कुओं में लीचिंग पाउडर डलवाने दिये निर्देश

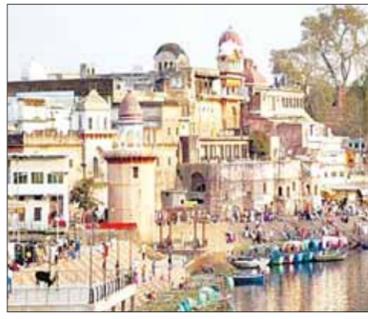
नगरनिगम आयुक्त ने कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को निर्देशित किया है कि वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये शहर के सभी कुओं में निर्धारित अनुपात में ब्लौचिंग पाउडर एवं कैल्सियम की गोलिएं डलवायी जाये ताकि पानी शुद्ध रहे एवं जलजनित बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। डॉ.मीना ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को भी निर्देश दिये हैं कि हेण्डपंप एवं पानी पंप के आसपास के गड्ढे साफ कराये जायें, जिससे वहां पानी का जमाव न हो। गड्ढों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया जाये।

सीवर लाइन बिछाने में मनमानी का मामला विधायक ने विधानसभा में उठाया

सतना। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने नगर निगम द्वारा सीवर लाइन डालने में की जा रही गड़बड़ी और उससे उपजे जनान्द्रोश के संबंध में विधानसभा में लिखित ध्यानाकर्षण सूचना दी है। जिसमें कहा गया है कि नगर पालिक निगम के वार्ड क्र.1 से 45 तक सीवर लाइन प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इस अव्यवस्थित खुदाई के कार्य से पूरे शहर में हाहाकार मचा है। सीवर लाइन अत्यन्त निम्न स्तर की एवं बेहद छोटे डायमीटर की डाली जा रही है जो आगे चलकर जगह जगह फूट जायेगी। चेम्बर जो बनाये जा रहे हैं वे अभी ही जगह जगह टूट गये हैं। सीवर लाइन एवं चेम्बरों को बनाने में ढाल वाटर लेवल तक का ध्यान नहीं रखा गया है। सीवर लाइन टेण्डर में खुदाई के बाद होने वाले रेस्टोरेशन वर्क सड़कों को वापस उसी स्वरूप में ठीक

करने का नियम व प्रावधान तक नहीं रखना एक पडयंत्र है। सतना शहर के निवासियों के साथ इस सीवर लाइन प्रोजेक्ट में खुल्लम-खुल्ला धोखा किया गया है जिसकी जांच राज्य शासन को मुख्य तकनीकी परीक्षक से तत्काल करवा कर प्रकरण को लोकायुक्त/ ई.ओ.डब्ल्यू में पंजीबद्ध करवाकर-निविदा बनाने वालों एवं घटिया स्तर की पाईप लाईन जो अत्यन्त छोटी है कि तकनीकी स्वीकृति देने वालों को तत्काल निलंबित करना चाहिये। पूरे शहर गड्ढों में तब्दील हो गया है। बरसात में हालात बेकाबू हैं। निगम रेस्टोरेशन के अब टेंडर निकाल रहा है जो बेहद आपत्तिजनक व शहर के करदाता निवासियों के साथ खुल्लम-खुल्ला मजाक है। लोक महत्व के बेहद गंभीर इस विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

चित्रकूट के पौराणिक महत्व वाले 9 स्थान रेखांकित



बजट में सतना की बड़ी हिस्सेदारी

सतना। मध्यप्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के पिटारे से राम वन पथ गमन के विकास के लिए निकली सौगात में से सतना की हिस्सेदारी बड़ी होगी। सरकार की तरफ से किए गए 34 करोड़ के बजट प्रावधान में सर्वाधिक राशि सतना के हिस्से में आएगी। सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल में साढ़े 11 वर्ष का लंबा समय व्यतीत किया था। इस दौरान वे इस अंचल के विभिन्न स्थानों पर गए थे, जिनका पौराणिक और धार्मिक महत्व आज भी है। श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्रीराम के वन गमन क्षेत्र में बिखरी धरोहरों को संरक्षित करने के लिए रामवन गमन पथ विकास प्रोजेक्ट बनाया है।

सतना। मध्यप्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के पिटारे से राम वन पथ गमन के विकास के लिए निकली सौगात में से सतना की हिस्सेदारी बड़ी होगी। सरकार की तरफ से किए गए 34 करोड़ के बजट प्रावधान में सर्वाधिक राशि सतना के हिस्से में आएगी। सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल में साढ़े 11 वर्ष का लंबा समय व्यतीत किया था। इस दौरान वे इस अंचल के विभिन्न स्थानों पर गए थे, जिनका पौराणिक और धार्मिक महत्व आज भी है। श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्रीराम के वन गमन क्षेत्र में बिखरी धरोहरों को संरक्षित करने के लिए रामवन गमन पथ विकास प्रोजेक्ट बनाया है।

34 करोड़ रुपए का प्रावधान

इस प्रोजेक्ट के लिए इस बार बजट में किए गए 34 करोड़ रुपए के प्रावधान का लाभ चित्रकूट क्षेत्र को मिलेगा। हालांकि यह राशि प्रदेश के 9 जिलों के विहित 23 स्थानों पर खर्च की जागी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सतना जिले के चित्रकूट अंचल की होगी। क्योंकि प्रदेश भर में विहित 23 स्थानों में से सर्वाधिक 9 स्थान सतना में हैं जिनके पड़ोसी जिले पन्ना में भी 4 स्थान विहित हैं।

सतना के और क्या ?

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के वनवास काल से जुड़ी कई धरोहर चित्रकूट क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। इनमें स्फटिक शिला, सती अनुसुइया आश्रम, सरमंगा, अत्रि गुनि का आश्रम, सुरीहंग आश्रम, श्रीराम प्रतिष्ठा स्थल सिद्धा पर्वत गुप्त गोदावरी तथा रक्वेलवा में राम शैल व सीता रसोई जैसे पवित्र स्थान हैं। इसी तरह पन्ना में बृहस्पति कुंड, अग्निजिह्वा तथा अगस्त्य गुनि आश्रम तथा शारंगधर आश्रम हैं।

मोदी जी हमारे यहां रोड़ तो बनवाय देई...



सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में महिला ने पीएम मोदी से सड़क बनवाने की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि हमने आपको 29 की 29 सीटें जितकर दी हैं। अब सड़क बनवा दीजिए। महिला वीडियो में ही कहती है कि सड़क को लेकर विधायक, कलेक्टर, सांसद सबसे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी सड़क नहीं बन पाई है। बारिश के समय में यहां की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके साथ ही महिला ने सड़क की मौजूदा स्थिति भी वीडियो में दिखाई है। बहरहाल अब देखा होगा कि महिला के वीडियो वायरल होने के बाद सड़क बनाई जाती है या फिर तब तक इंतजार अभी और करना पड़ेगा।

सतना। मध्यप्रदेश में सड़कों की हालात किसी से छिपी नहीं है। सरकार लाख दावे करे अपने विकास का लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित है। हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार जीत मिली है। इस जीत के बाद मध्य प्रदेशवासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। यही कारण है कि अब लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र के एक गांव वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला ये कहती नजर आ रही है कि हमारे यहां रोड़ तो बनवाय देई, हमने पूरी 29 की 29 सीटें आपको जितवाई, ये रोड़ देखें, कबाड़ है! हमारे यहां के लोग सांसद, विधायक, कलेक्टर तक से मिले, लेकिन कोई नहीं सुनता, मेरा गांव खड्डी खुर्द, जिला

कछुआ गति से किया जा रहा है सीएम राइज स्कूल के भवन का निर्माण

मैहर। भवन न बन पाने से सीएम राइज स्कूल मैहर में अव्यवस्थाओं का आलम है। माँ शारदे की धार्मिक नगरी में सीएम राइज स्कूल खुल चुका है एवं कक्षाएं भी वगत वर्षों से पुराने भवन में प्रारंभ हैं। शेष भवन को तोड़कर नई बिल्डिंग का निर्माण भी किया जा रहा है किंतु अभी तक बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया है जिसके कारण काफी परेशानी का सामना छात्र-छात्राओं को करना पड़ रहा है। सत्र प्रारंभ हो गया है किंतु विद्यालय भवन तैयार नहीं हो सका। विद्यालय निर्माण एजेंसी पीआईड्यू द्वारा पुराना भवन तोड़ते समय सत्र प्रारंभ होने के पूर्व अप्रैल 2024 में एक ब्लाक पूर्ण कर देने की बात कही थी। किंतु आज तक कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके विपरीत पीआईड्यू के अधिकारियों द्वारा विद्यालय को जर्जर यात्री निवास क्रमांक 3 में शिफ्ट करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2024 को संभागीय परियोजना यंत्रोपीआई यू लोक निर्माण विभाग सतना को सीएम राइज स्कूल मैहर का भवन तैयार कर उपलब्ध कराने का कठ कर। ताकि कक्षाओं का नियमित संचालन किया जा सके।



विषयक पत्र लिखा जा चुका है। कि नवीन भवन निर्माणधीन है जिसके तहत पूर्व निर्मित सभी कक्षाएं तोड़ी जा चुकी हैं। निर्माण एजेंसी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सत्र 2024, 25 के प्रारंभ में एकडेमिक ब्लॉक एवं दक्षिण दिशा का पूरा ब्लॉक तैयार करके पूरा कर दे दिया जाएगा परंतु अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया है। प्राचार्य द्वारा ठेकेदार से जब जानकारी मांगी गई तब ठेकेदार ने कहा कि संबंधित ब्लॉक का प्लास्टर आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है फिनिसिंग तथा खिड़की दरवाजे से संबंधित ड्राइंग प्राप्त न होने के कारण फरवरी 2024 से आगे का कार्य रुका हुआ है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 अध्यापन कार्य हेतु विद्यालय में कक्ष उपलब्ध नहीं है तथा पुराने भवन के कक्ष भी निर्माण एजेंसी द्वारा गिरा दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में कक्षाओं का संचालन करने में कठिनाई हो गई है। सीएम राइज स्कूल मैहर का नवीन भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराकर विद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध कराने का कठ कर। ताकि कक्षाओं का नियमित संचालन किया जा सके।

किसी भी हालात में लौटने को नहीं राजी दोनों हाथी

अनूपपुर। जिले में विगत 19 दिन से छत्तीसगढ़ राज्य से आए दो नर हाथियों ने निरंतर अनूपपुर एवं जैतहरी क्षेत्र के जंगलों में दिन में ठहरने बाद रात होते ही आसपास के ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं खेत एवं बाड़ी में लगे विभिन्न तरह के फलों तथा फसलों को अपना आहार बना रहे हैं। हाथियों को जिले से बाहर किये जाने हेतु प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा निरंतर नए-नए तरीके से प्रयोग किया जा रहा है किंतु दोनों हाथी वापस जाने को किसी भी तरह तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। विगत दिनों कुछ गांव में कुछ ग्रामीणों द्वारा हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए खेतों एवं घरों के आसपास गैर कानूनी किस्सी और अपना रुख करने यह देर रात होने पर ही पता चल सका। हाथियों के विचरण पर अनूपपुर वन मंडलाधिकारी सुश्री श्रद्धा पेन्डे वनविभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ निरंतर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ग्रामीणों को हाथियों के पीछे-पीछे न चलने, हाथियों का रास्ता न रोकने, अपने खेतों व घरों के आसपास गैर कानूनी सामग्रियों का उपयोग न किए जाने जैसी सलाह दी जा रही है। विगत दिनों कुछ गांव में कुछ ग्रामीणों द्वारा हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए खेतों एवं घरों के आसपास आपत्तिजनक सामग्रियों का प्रयोग किए जाने की गोपनीय सूचना पर वन विभाग के द्वारा डांग एस्कॉर्ट गैरडोलेट के माध्यम से जगह-जगह गोपनीय तरीके से परीक्षण कराए जाने की कार्यवाही भी की जा रही है ताकि ग्रामीणों की नासमझी से फिर कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो सके।

कोतमा में लगातार हो रही चोरी की वारदात

पुलिस की निष्क्रियता पर उठ रहे सवाल

कोतमा। क्षेत्र में बेतहाशा हो रही चोरी की घटनाओं ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आए दिन घरों एवं दुकानों के ताले टूट रहे हैं। बीच बाजार खड़ी दो पहिया वाहन की चोरी सहित धार्मिक स्थल मंदिरों में लगातार हुई चोरी ने नगरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। चार दिनों के अंदर दो चोरी की घटनाएं घटित हुईं। कपड़ा व्यापारी विपुल गौयनका के यहां गोदाम में हुई लाखों की चोरी की जांच अभी चली रही थी कि रविवार साप्ताहिक बाजार के दिन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश ताम्रकार जो सब्जी खरीदने बाजार आए थे आजाद चौक के समीप किसी अज्ञात जेब कर्ते द्वारा उनकी जेब को काटते हुए वीवो कंपनी का कीमती मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की शिकायत भाजपा नेता द्वारा थाना कोतमा में दी गई जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में कुछ संदेहियों को थाने लाकर पृष्ठताछ प्रारंभ कर दी थी। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से नगर के व्यापारी एवं आम नागरिक भयभीत हैं। पुलिस के द्वारा अभी तक नगर में हुई एक दर्जन से ज्यादा चोरियों का खुलासा करने में नाकाम साबित हो



रही है। वहीं पुलिस के द्वारा दो पहिया वाहन चोरी एवं नगर के व्यापारी विपुल गौयनका के गोदाम में हुई लाखों की चोरी का मामला भी दर्ज नहीं कर पाई है। पूर्व में नगर के वार्ड क्रमांक एक फिल्टर मोहल्ला में 8 जून की रात्रि सोल भद्र जोशी की दो पहिया वाहन चोरी हो गई थी जिसकी शिकायत लिखित में उनके द्वारा खाने में दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस के द्वारा 18 दिन बाद 26 जून को दो पहिया वाहन चोरी का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही लगातार नगर से दो पहिया वाहन चोरी की घटना घटित हो रही है। इसके पूर्वी नगर के वार्ड क्रमांक 7 ज्योति पेट्रोल पंप के पीछे

निवास करने वाले शिक्षक सुधीर सक्सेना के सून घर से दो-तीन मार्च की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ते हुए घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 20 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। इसी तरह नगर के शारदा काली मंदिर में दो बार अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नगर के बस स्टैंड में स्थित गणेश मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर में लगी घंटी एवं लोहे का गेट चोरी कर ले गए। नगर के पंचायती मंदिर के पास आशोक जैन के कपड़ा दुकान में छपूर तोड़ते हुए अज्ञात चोरों ने दो बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नगर के वार्ड क्रमांक 10 में पान दुकान का ताला तोड़ते हुए दुकान में रखे गैस सिलेंडर चूल्हा सहित दुकान का पूरा सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक चोरों का पता लगाने में नाकाम साबित हुई। नगर में आए दिन हो रही चोरी की घटना को लेकर नागरिकों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों एवं नागरिकों का कहना है कि यदि पुलिस के द्वारा नगर में हो रही चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई तो हम लोग पुलिस अधीक्षक एवं मध्यप्रदेश के मंत्री दिलीप जायसवाल को ज्ञापन देते हुए आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर हो जाएंगे।

संपत्ति कर जमा नहीं करने पर मैरिज गार्डन में नगर निगम ने लगाया ताला

सतना। निगम प्रशासन द्वारा संपत्ति कर एवं अन्य संलग्न करों के बकायादारों के बकाया कर की अद्यतन राशि वसूल किये जाने के लिये आयुक्त डॉ.शेर सिंह मीना के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 15 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। नगरनिगम के जनसंपर्क अधिकारी अनिल श्रीवास्तव के अनुसार उक्त कार्यवाही सहायक आयुक्त एच एम श्रीवास्तव के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों की टीम द्वारा की गयी। बताया गया है कि वार्ड क्र.1 रीटम संस्कार मैरिज गार्डन के संचालक विनोद कुमार तिवारी पर सन 2020 से अभी तक का संपत्ति कर एवं संलग्न कर 2 लाख 52 हजार 44 रुपये बकाया था। जिसकी वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस दिये जाने पर इनके द्वारा राशि जमा नहीं करायी गयी। अतएव नगरनिगम आयुक्त के आदेश पर मैरिज गार्डन में ताला बंदी की कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही में सहायक राजस्व अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, प्रभारी राजस्व निरीक्षक रमेश मिश्रा, राजस्व निरीक्षक राजनीश मिश्रा, उप राजस्व निरीक्षक अनुराग सिंह, नागेश चतुर्वेदी एवं सहायक राजस्व निरीक्षक राजकिशोर कुशवाहा, शुभम सेन, अनुपम पाण्डेय एवं संपत्ति कर शाखा के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सहायक आयुक्त एचएम श्रीवास्तव ने नगर निगम के सभी मैरिज गार्डन संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बकायादारों से अनुरोध किया है कि वे अपने बकाया करों की राशि तत्काल निगम कार्यालय पहुंच कर जमा करायें अन्यथा नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।

खबर संक्षेप

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 9 जुलाई को

पन्ना जिला पंचायत की सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आगामी 9 जुलाई को होगी। जिला पंचायत सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे से सामान्य सभा की बैठक में पीडब्ल्यूडी, अटल भू जल, जल जीवन मिशन एवं खनिज विभाग की समीक्षा होगी। इसी तरह 4 बजे से आयोजित सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा सहित अन्य निर्धारित एजेण्डा पर चर्चा की जाएगी।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ प्रिय द्वारा बैठक में संबंधित जनप्रतिनिधियों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जन सुनवाई में ध्यानपूर्वक सुनें एवं निराकरण के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें - कलेक्टर

कलेक्टर सुरेश कुमार ने प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बेहतर

क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर सहित अनुविभाग, तहसील, थाना, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर के समस्त शासकीय कार्यालयों में

जनसुनवाई कार्यक्रम के लिए व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जाए। इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि कार्यालय में जनसुनवाई का स्थान निर्धारित कर सहज दृश्य स्थल पर जनसुनवाई के लिए समय सुविधा करने संबंधी बोर्ड लगाएँ और जनसुनवाई व्यवस्था का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करें।

जनसुनवाई में पहुंचे आम नागरिकों से शिष्ट एवं विम्वक्य बर्तन कर उनकी शिकायतों और बातों को ध्यानपूर्वक सुनें एवं निराकरण के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। किन्हीं कारणोंवश नियमों के अधीन शिकायत या मांग की पूर्ति नहीं होने पर कारण सहित सूचित भी किया जाए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन व शिकायतों की मॉनीटरिंग और निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रारूप में पंजी संघारित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

जिला कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलने तथा आवेदनों और शिकायतों का यथासंभव जनसुनवाई दिवस पर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिक समय की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक न्यूनतम अवधि में शिकायत व आवेदन का निराकरण करने के लिए कहा है।

सभी कार्यालयों में जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित कर सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में निर्धारित समय पर जनसुनवाई कर अधीनस्थ विकासखण्ड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलने तथा आवेदनों और शिकायतों का यथासंभव जनसुनवाई दिवस पर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिक समय की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक न्यूनतम अवधि में शिकायत व आवेदन का निराकरण करने के लिए कहा है। सभी कार्यालयों में जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित कर सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में निर्धारित समय पर जनसुनवाई कर अधीनस्थ विकासखण्ड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलने तथा आवेदनों और शिकायतों का यथासंभव जनसुनवाई दिवस पर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिक समय की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक न्यूनतम अवधि में शिकायत व आवेदन का निराकरण करने के लिए कहा है। सभी कार्यालयों में जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित कर सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में निर्धारित समय पर जनसुनवाई कर अधीनस्थ विकासखण्ड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलने तथा आवेदनों और शिकायतों का यथासंभव जनसुनवाई दिवस पर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिक समय की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक न्यूनतम अवधि में शिकायत व आवेदन का निराकरण करने के लिए कहा है। सभी कार्यालयों में जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित कर सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में निर्धारित समय पर जनसुनवाई कर अधीनस्थ विकासखण्ड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलने तथा आवेदनों और शिकायतों का यथासंभव जनसुनवाई दिवस पर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिक समय की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक न्यूनतम अवधि में शिकायत व आवेदन का निराकरण करने के लिए कहा है। सभी कार्यालयों में जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित कर सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में निर्धारित समय पर जनसुनवाई कर अधीनस्थ विकासखण्ड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलने तथा आवेदनों और शिकायतों का यथासंभव जनसुनवाई दिवस पर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिक समय की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक न्यूनतम अवधि में शिकायत व आवेदन का निराकरण करने के लिए कहा है। सभी कार्यालयों में जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित कर सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में निर्धारित समय पर जनसुनवाई कर अधीनस्थ विकासखण्ड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलने तथा आवेदनों और शिकायतों का यथासंभव जनसुनवाई दिवस पर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिक समय की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक न्यूनतम अवधि में शिकायत व आवेदन का निराकरण करने के लिए कहा है। सभी कार्यालयों में जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित कर सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में निर्धारित समय पर जनसुनवाई कर अधीनस्थ विकासखण्ड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

मानसून पर्यटन को लेकर पन्ना में कई प्राचीन स्थल तथा झरने पर्यटकों का बन सकते हैं आकर्षण का केन्द्र

पर्यटन से ही विकास व रोजगार के खुलेंगे द्वार



पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर देखने व दिखाने वाले तथा इससे जुड़े हजारों लोगों को रोजगार तय होता है मात्र एक टाइगर को एक झलक पाने को लेकर जिले में पर्यटन की संभावनायें तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक ने जो समृद्धता प्रदान की है वह अलग ही देखने में मिलती है अन्य जिलों की तुलना में पन्ना पर्यटन को लेकर विकास की दिशा तय करने के लिये माना जा रहा है। यहां मानसून पर्यटन को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल से ही योजना चर्चा में रही पर आज तक पटल पर क्रियान्वयन के रूप में तय नहीं हो सकी। सबसे बड़ी जरूरत जहां आज अन्य जिलों से हटकर पन्ना में विकास को

लेकर जो उम्मीदें सजाई गई थी वह आज भी अधूरी है उदाहरण को लेकर पर्यटन से किस तरह से रोजगार तथा विकास दोनों तय होते हैं वह पन्ना टाइगर रिजर्व तथा आस-पास बने रिसॉर्टों से ही जाना जा सकता है। एक टाइगर की झलक पाने को लेकर जिस तरह से टाइगर रिजर्व में रोजगार की संभावनायें जो मानी जाती थी वह आज सपने साकार करने को लेकर साबित हो रही है। एक टाइगर से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं पर्यटन से पर्यटकों के माध्यम से जिले को लाभ के हालात अलग ही तय हो रहे हैं। एक टाइगर की झलक पाने को लेकर पर्यटक दूर-दूर से देशी व विदेशी पन्ना टाइगर रिजर्व में पहुंचते हैं जिसमें जिप्सी वाहन

होटल व रिसॉर्ट तथा गाइड वहीं इससे जुड़े हुये लोग जो रोजी-रोटी के साथ-साथ रोजगार को लेकर अपने जीवन को आज नई दिशा दे रहे हैं। पन्ना जिले की केन नदी जो मड़ला गांव के पास विकास को लेकर यहां अगल-बगल यहां पन्ना हो या छतरपुर जिले की सीमा में टाइगर रिजर्व के कारण अलग ही जमीन की कीमत से लेकर पर्यटन से जुड़े हुये व्यवसाय तथा रिसॉर्टों से बदलाव विकास का बयां कर रहा है। इसी तरह मानसून पर्यटन की शुरूवात होगी तो निश्चित ही इसके विकास में हटकर यह जिला साबित होगा। पन्ना में कई प्राचीन समय से इतिहास को बयां कर रहे धार्मिक स्थल के रूप में प्राचीन मंदिर तथा यहां के झरने जो पहाड़ों से नदियों में

प्रवाहित होकर पहुंचते हैं पर इनकी सुंदरता मानसून या बारिस के समय अलग ही जानी जाती है तभी तो बृहस्पित कुण्ड में जो नये आयाम से भावी सोच के साथ ग्लास ब्रिज के माध्यम से पर्यटकों को झरने के दीदार कराये जाने को लेकर कार्य अंजाम देने के लिये प्रयास जारी है वहीं पन्ना जिले में कई ऐसे पहाड़ों में सौंदर्य को लेकर बारिस के समय अन्य झरने भी अपनी छटा बिखेरते हैं साथ ही प्राचीन धरोहरें स्टेड के जिले में अपने प्राचीन समय की कला को लेकर अपनी भव्यता बयां करते हैं वहीं पन्ना जिला मुख्यालय में स्वयं ही महेन्द्र भवन तथा यहां का राज निवास पैलेस जो अपनी स्टेड के समय की कला कारीगरी तथा भव्यता पर्यटकों

के लिये आकर्षण का केन्द्र मानी जाती है। पर्यटन से ही पन्ना के विकास को अलग ही अन्य जिलों की तुलना में विकास की दिशा तय करने में म.प्र. के साथ-साथ देश-दुनिया में पन्ना को हीरो की तरह पर्यटन के क्षेत्र में भी चमक बिखरने को लेकर जाना जा सकता है। वहीं रोजगार के अवसर विकास के साथ-साथ पर्यटन की संभावनाओं से ही संभव हो सकते हैं जिस तरह से पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर की एक झलक पाने से आज हजारों लोगों को रोजगार मिलने की दिशा तय हो रही है इसी तरह मानसून पर्यटन व यहां की पर्यटन की संभावनाओं से पन्ना विकास के कई आयाम तय करने को लेकर दुनिया में जाना जायेगा।

नवीन पोर्टल पर जन्म-मृत्यु के ऑनलाइन पंजीयन के संबंध में हुआ प्रशिक्षण



रजिस्ट्रार के निर्देशन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नवीन पोर्टल रीवैम्पड विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आमजन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा। नवीन पोर्टल संचालन के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर सभाकक्ष पन्ना में जनगणना निदेशालय भोपाल से आये प्रशिक्षक प्रेमा नायर और अभिषेक सिंह ठाकुर द्वारा जिले के रजिस्ट्रारों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला योजना अधिकारी अल्का रजनी दास एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी राजीव कपटल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पन्ना। जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। संशोधित अधिनियम-2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नवीन पोर्टल रीवैम्पड विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आमजन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा। नवीन पोर्टल संचालन के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर सभाकक्ष पन्ना में जनगणना निदेशालय भोपाल से आये प्रशिक्षक प्रेमा नायर और अभिषेक सिंह ठाकुर द्वारा जिले के रजिस्ट्रारों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला योजना अधिकारी अल्का रजनी दास एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी राजीव कपटल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

प्रदेश अध्यक्ष बीडी. शर्मा व पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह के प्रयास से अमानगंज से पवई रेल लाइन की स्वीकृत

पवई। प्रदेश में सबसे अधिक पिछड़ा पन्ना जिला की पवई तहसील आजादी के 75 वर्षों के बाद भी संसाधनों से विहीन है। जबकि पवई विधान सभा क्षेत्र खजुराहो लोक सभा अन्तर्गत आता है। खजुराहो सांसद आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी द्वारा एवं पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री द्वारा अमानगंज से पवई नवीन रेलवे लाइन स्वीकृत कराई गई है बहुत-बहुत बधाई शुभकामनाएं धन्यवाद आभार पवई में रेलवे लाइन स्वीकृत करने की। वेरोजगारी एवं गरीबी के चलते रोजगार की तलाश में हजारों लोग बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। काफी समय से पवई के समाज सेवा प्रहलाद बेहरे सहित क्षेत्र के लोगों द्वारा रेल लाइन के लिए



आवाज उठाई जा रही है कई बार रेल मंत्री के नाम एस डी एम से लेकर मुख्यमंत्री सांसद विधायक को ज्ञापन प्रहलाद बेहरे द्वारा दिया

जाता था। कुछ दिनों से एक पत्र रेलवे मंत्रालय के जबलपुर मंडल से जारी हुआ नवीन रेल लाइन स्वीकृत पत्र सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमे अमानगंज से पवई 23 किलो मीटर रेल लाइन की स्वीकृत के साथ 57 लाख 50 हजार की राशि स्वीकृत की गई है अमानगंज से पवई रेल लाइन की स्वीकृत मिल चुकी है। यदि सही है तो सर्वे का काम कब तक शुरू होगा यह बात पवई अमानगंज के लोगो मे चर्चा का विषय बनी हुई है। पवई रेलवे स्टेशन का नाम मां कलेही रेलवे स्टेशन पवई जिला पन्ना मध्य प्रदेश किया जाए हनुमान भाटे के श्री हनुमान जी भगवान की जय हो कलेही माता की कृपा से आप सब पर बनी रहे।

उप जेल पवई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, किया वृक्षारोपण

पन्ना। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भावना साधो के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश व प्राधिकरण के सचिव हरप्रसाद साधोकार की अध्यक्षता में आज उप जेल पवई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में उप जेल द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही जेल प्रबंधन को बंदियों के जमानत आदेश प्राप्त होने के सात दिवस में बंदी की रिहाई नहीं होने पर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों की भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा बंदियों को जेल में अनुशासन बनाए रखने और स्वयं के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया गया। बंदियों को अधिवक्ता की आवश्यकता पर जेल प्रशासन के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने संबंधी जानकारी भी दी गई। बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही कर जरूरतमंद को पैनल से निःशुल्क अधिवक्ता



उपलब्ध कराया जाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने उपस्थित बंदियों को प्ली बारगेनिंग के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान कर जेल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य मामलों में समझौता कर सुलह की सलाह दी। बंदियों के विधिक अधिकार और कर्तव्य भी बताए। इसके अतिरिक्त लोक अदालत, मध्यस्थता और बंदियों के

अधिकारों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। शिविर के समापन पर सहायक जेल अधीक्षक मुनीन्द्र मिश्रा द्वारा आभार प्रदर्शन कर बंदियों को शिविर से प्राप्त विधिक जानकारी को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिविर उपरांत जेल परिसर में पंच-ज अभियान के तहत जामुन, अमरूद, शीशम, बबूल, आंवला इत्यादि के लगभग 50 पौधे रोपित किए गए।

नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का प्रशिक्षण संपन्न

पन्ना। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का प्रशिक्षण गुरुवार को जिले के निर्धारित स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी व अन्य संबंधित कर्मचारी भी उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर 2024 को होगा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 4 जुलाई तक प्रदान किया जाना था। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 19 जुलाई को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्ति 19 जुलाई से 2 अगस्त तक लिए जाएंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 9 अगस्त है। फोटोयुक्त



अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 12 सितंबर 2024 को किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया नियमानुसार निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।



पोषण पुनर्वासि केंद्र में कुपोषित मनीष को मिला पुनर्जीवन

पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कुपोषण की समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है। भीषण गरीबी से जूझ रहे आदिवासी परिवारों के मासूम कुपोषण के सर्वाधिक शिकार हैं। कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। दूरदराज के आदिवासी बहुल इलाकों में मासूम बच्चों के साथ-साथ महिलाएं भी कुपोषण की समस्या से जूझ रही हैं। पन्ना जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित मनौर गांव का गुडियाना टोला कुपोषण और सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए जाना जाता है। इस गांव में कई लोगों की मौत सिलिकोसिस से हुई है। तकरीबन ढाई सौ घरों वाली इस आदिवासी बस्ती में 30 से अधिक विधवा महिलाएं हैं। भीषण गरीबी, कुपोषण व वेरोजगारी इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है। मनौर गांव वर्षीय आदिवासी बालक मनीष भी गंभीर रूप से कुपोषित था, जिसे पिछले दिनों पोषण पुनर्वासि केंद्र पन्ना में भर्ती कराया गया। पोषण पुनर्वासि केंद्र पन्ना में पदस्थ रश्मि त्रिपाठी ने बताया कि जब इस बच्चे को भर्ती करने के लिए पन्ना लाया गया, उस समय वह गंभीर रूप से कुपोषित था। इसका वजन महज 4 किग्रा के आसपास था, लेकिन पोषण पुनर्वासि केंद्र में समुचित



देखरेख और इलाज होने पर 22 दिनों में ही इस बालक की हालत में सकारात्मक सुधार हुआ और वजन 4 किग्रा से बढ़कर 6.5 किग्रा हो गया। इस बालक की मां ने बताया कि उन्हें बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा यह बच्चा बीमारी (कुपोषण) से उबर पायेगा। हम लोग पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे, लेकिन पन्ना में इलाज होने और पीछे खाना मिलने से मनीष अब अच्छा हो गया है। कुपोषण की यह समस्या सिर्फ मनौर गांव में ही नहीं है, यहाँ आसपास जितने भी आदिवासी गांव हैं वहाँ कुपोषित बच्चे

बड़ी तादाद में हैं। रश्मि त्रिपाठी ने बताया कि मनौर के अलावा पन्ना से लगे बड़ौर, मनकी, जरधोवा व सुनहरा आदि ग्रामों से भी कुपोषित बच्चे पोषण पुनर्वासि केंद्र में आते हैं। देवेन्द्रनगर क्षेत्र के आदिवासी बहुल ग्रामों में भी कुपोषण की समस्या गंभीर है। आपने बताया कि पोषण पुनर्वासि केंद्र पन्ना में भर्ती कराए गए गंभीर कुपोषित बच्चे मनीष आदिवासी को पुनर्जीवन मिला है। अब मनीष पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका वजन बढ़ने लगा है। मनीष की मां जयंती पोषण पुनर्वासि केंद्र पन्ना में हुए इलाज के उपरांत बालक मनीष के पूरी तरह स्वस्थ होने पर बेहद खुश है। जो बालक कुछ दिनों पूर्व तक अत्यधिक कमजोरी के कारण लाचार और बेवस पड़ा रहता था, अब वह खेलने लगा है तथा उसका वजन भी बढ़ रहा है। रश्मि त्रिपाठी बताती हैं कि मनौर गांव के बालक मनीष आदिवासी को अप्रैल माह में पन्ना पोषण पुनर्वासि केंद्र में भर्ती कराया गया था, उस समय उसका वजन मात्र 4 किलो था। सरकार के मापदंड और पोषण पुनर्वासि केंद्र की व्यवस्थाओं के अनुसार उसे डॉक्टरों इलाज और पोषित भोजन दिया गया। जिससे बालक का वजन बढ़ने लगा, अब वह पूरी तरह तंदुरुस्त है। मनीष आदिवासी का वजन बढ़ाकर 4 किलो से साढ़े 6.5

किलो हो गया है। आपने ने बताया कि जब पहली बार पोषण पुनर्वासि केंद्र में मनीष को लाया गया, तब कुपोषित मनीष आदिवासी के शरीर में मात्र एक ग्राम हीमोग्लोबिन बचा था। रश्मि त्रिपाठी ने बताया कि डेढ़ वर्षीय मनीष आदिवासी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण पुनर्वासि केंद्र लेकर आई थी, साथ में उसकी मां जयंती आदिवासी थी। बालक का पिता आलू गोड मजदूरी करने दिल्ली गया हुआ था, जब उस खबर मिली कि उनका बच्चा मनीष स्वस्थ होकर खेलने लगा है तो पिता अपने को रोक नहीं पाया और वह दिल्ली से बच्चे को देखने मनौर पहुंच गया। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि मनीष की तरह अक्सर कुपोषित बच्चे पोषण पुनर्वासि केंद्र में आते हैं, जिन्हें हम पोषित भोजन और इलाज देते हैं। यहाँ आने वाले अधिकांश कुपोषित बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, मनीष आदिवासी एक उदाहरण है जिसकी बीमारी दूर हुई है और वजन तेजी से बढ़ा है। डॉ. गुप्ता ने अपील की है कि बरसात के सीजन में बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है, लिहाजा मातायें अपने बच्चों को साफ सुथरा रखें और गंदगी से बचाव करें। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो अस्पताल लाकर डॉक्टरों इलाज अवश्य करावें।

खबर संक्षेप

5 हजार के फरार इनामी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा छतरपुर। बीते दिनांक 20 जून को थाना गढ़ी मलहरा क्षेत्र के ग्राम गुरसारी में विवाद व मारपीट होने को सूचना प्राप्त हुई थी। पीड़ित को गांव के लोगों द्वारा गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर थाना गढ़ी मलहरा में मारपीट, हत्या का प्रयास एवं जान से मारने संबंधी धाराओं में नामजद आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी गढ़ीमलहरा धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित पांच हजार के इनामी दो आरोपी गजराज यादव एवं चरण यादव निवासी ग्राम गुरसारी थाना गढ़ी मलहरा को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तों को न्यायालय पेशकर जेल भेजा गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गढ़ीमलहरा निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह उन निरीक्षक अजीत टोप्यो, सहायक उप निरीक्षक संतोष सिंह, प्रधान अपरक्षक शैलेंद्र सिंह, जनक सिंह, प्रदीप तिवारी, अपरक्षक दशरथ को मुख्य भूमिका रही। चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र की जांच के लिए टीम गठित होगी

संयुक्त संचालक ने संमाला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक का प्रभार

छतरपुर। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर के महाप्रबंधक का प्रभार बुधवार शाम संयुक्त संचालक राजशेखर पांडे ने संभाल लिया। चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र के भूमि आवंटन में मनमानी पर महाप्रबंधक आशुतोष गुप्ता और प्रभारी प्रबंधक श्रीप्रकाश मिश्रा को दो दिन पहले सस्पेंड कर दिया था। श्री पांडे ने बताया कि चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर सूक्ष्मा से जांच करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसी मामले में मनमानी के चलते दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है।

7 दिवस में नहीं हुई मांगे पूरी तो डाल देंगे विश्वविद्यालय में ताला: नीतेश तिवारी

छतरपुर। शिवसेना की छात्र इकाई भारतीय विद्यार्थी सेना द्वारा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम में हुई त्रुटी एवं तालाशाही रवैया को लेकर घेराव किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है जिसको लेकर विश्वविद्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है उसमें लगभग 20 प्रतिशत छात्रों को उत्तीर्ण किया गया जबकि लगभग 80 प्रतिशत छात्रों को या तो फ़ैल कर दिया जाता है या एटीकेटी दे दी जाती है जो छात्र फ़ैल होने या एटीकेटी आने के बाद छात्र आरटीआई लगाकर कॉपी दी जाती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा की गई गलतियाँ जैसे त्रुटि पूर्ण तरीके से कॉपी चेक करना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही होने पर भी अंक नहीं देना, कई प्रश्न सही होने पर भी कम नंबर देना इस प्रकार से कई त्रुटियाँ पाई जाती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में उपस्थित छात्रों को भी अनुपस्थित कर फ़ैल कर दिया जाता है।

अवैध शराब की बिक्री पर नहीं लग पा रहा अंकुश टी आई मोरवा की मिलीभगत...?

सिंगरौली। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश शासन व भारत सरकार के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, वहीं नियमों की ताक पर थाना प्रभारी मोरवा के संरक्षण में खुलेआम शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री घड़ल्ले से चल रही है, ऐसे में सवाल ये उठता है की क्या थाना प्रभारी इतने संतुष्ट हैं गोरख धंधे में, कि जरा सा भी आम नागरिक व समाज का ध्यान नहीं है। या फिर जानबूझ ईमानदारी का चोला ओढ़कर मलाई काट रहे हैं? गली, चौराहों की चर्चा बने हैं थाना प्रभारी मोरवा कोयला कबाड़ चोरों का भी बोलबाला जोरों पर इनसे भी मिलीभगत से काट रहे हैं चांदी।

बैंक बीते कुछ माह बिना प्रशासक के ही सभी प्रकार के कामकाज निपटाता रहा

छतरपुर। सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छतरपुर के बैंक सीईओ मनोज कुमार सक्सेना और प्रशासक के पद पर डीआर सहकारिता डॉक्टर अरुण मसराम ने बीते 25 जून को बैंक में ज्वाइन कर लिया। बीते कुछ दिनों पहले सद्भाव नागरिक सहकारिता बैंक में प्रशासक के पद पर जेआर सागर ने संजय बुधोलिया को नियुक्त किया था, जो कि सहकारिता ऑफिस में वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन आदेश में पुनः परिवर्तन होने के बाद जेआर सागर ने डीआर सहकारिता छतरपुर डॉक्टर अरुण मसराम को प्रशासक के पद पर नियुक्त किया है। बीते साल 10 मई 2023 में वित्तीय लेनदेन के आरोप में बैंक सीईओ मनोज कुमार सक्सेना को निलंबित कर चार्ज वरिष्ठ लिपिक राकेश दीक्षित को सौंपा गया था। जिसमें तत्कालीन बैंक सीईओ मनोज कुमार सक्सेना को 25 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था। लेकिन अपात्र संचालक मंडल अध्यक्ष श्रीमती बाजपेई द्वारा श्री सक्सेना को ज्वाइन नहीं कराया गया। जिसमें ज्वानिंग को लेकर कई बार अपर कलेक्टर ने पत्राचार उपायुक्त सहकारिता छतरपुर, जेआर सागर सहकारिता को किया गया, लेकिन अपने रसूख के चलते संचालक मंडल अध्यक्ष ने ज्वाइन नहीं कराया था। सभी प्रकार की जांच में श्री सक्सेना निर्दोष होने पर जेआर

मनोज कुमार सक्सेना ने सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक सीईओ के पद पर किया ज्वाइन



सागर ने सीईओ के पद पर बैंक में पुनः 25 जून को मनोज कुमार सक्सेना को ज्वाइन कराया।

तया था पूरा मामला -

बीते साल 2023 में सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में आरबीआई ने संचालक मंडल के अध्यक्ष सहित 12 सदस्यों में से 7 सदस्यों को अपात्र घोषित किया था। जिसकी शिकायत लिखित में संयुक्त पंजीयक सहकारिता सागर में की गई थी। संयुक्त पंजीयक ने जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी गठित की थी। नियुक्त जांच दल ने भी संचालक मंडल के 12 में से लगभग 9 सदस्यों को अपात्र होने का उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया था। जांच कमेटी ने जांच पूर्ण होने के बाद संयुक्त पंजीयक सागर को सौंपी थी। जिसमें संयुक्त पंजीयक डॉक्टर शिवेंद्र देव पांडेय ने तत्काल संचालक मंडल को भंग कर प्रशासक के तौर पर एनएस चौहान एआर सहकारिता छतरपुर को नियुक्त किया था। जिसमें संचालक मंडल अध्यक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली थी कि संचालक मंडल को गलत तरीके से डॉक्टर शिवेंद्र देव

पांडेय संयुक्त पंजीयक सागर द्वारा भंग किया गया है। जिसमें संचालक मंडल को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। जिसमें अध्यक्ष वाजपेई सहित सदस्यों ने सद्भावना नागरिक सहकारी बैंक में अपने-अपने पद पर ज्वाइन कर लिया था। संचालक मंडल अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों ने 14 मार्च 2024 को सहकारिता ऑफिस छतरपुर में अपने- अपने व्यक्तिगत कार्यों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपे गए थे। जिसे बैंक के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 7 मार्च 2024 में प्रस्ताव क्रमांक 07 पर रखा जाकर स्वीकृत किया गया था। उक्त स्थिति में बैंक में फोरेम का अभाव हो गया था। जिसके चलते उपायुक्त सहकारिता छतरपुर ने प्रशासक की नियुक्ति के लिए संयुक्त पंजीयक सागर को सहपत्रों सहित पत्राचार किया था। जिसमें लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता का उल्लेख करते हुए प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई थी, और बैंक बीते कुछ माह बिना प्रशासक के ही सभी प्रकार के कामकाज निपटाता रहा। बीते 4 जून 2024 को चुनाव की घोषणा हुई और आचार संहिता हटते ही सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक में प्रशासक के पद पर जेआर सागर ने संजय बुधोलिया को नियुक्त किया था, लेकिन एक लंबे अंतराल में मंडिकल लीव पर जाने पर पुनः आदेश में परिवर्तन किया गया और उपायुक्त सहकारिता छतरपुर डॉक्टर अरुण मसराम को प्रशासक के पद पर नियुक्त किया गया।

लंबे समय से चला आ रहा था सेल्स टैक्स चोरी सरिया का व्यापार, विभाग सालों से था अनजान रायपुर से छतरपुर लाए गए फर्जी ईबे बिल वाले 50 लाख के सरिया से लदे ट्रक का पर्दाफाश

सटीक मुखबिर की सूचना पर यातायात ट्रैफिक पुलिस ने की बड़ी कर्यवाही

छतरपुर। जिले में सेल्स टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने रायपुर से छतरपुर लाए गए लोहे के सरिया से भरे एक ट्रक को मुखबिर की सूचना पर यातायात पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक चालक चांद खान के अनुसार, यह ट्रक रायपुर से छतरपुर आया था, और इसे नौगांव रोड स्थित राज धर्मकांटा पर उतारने के लिए कहा गया था। ट्रैफिक पुलिस ने सटीक मुखबिर की सूचना पर ट्रक क्रमांक यूपी 95 T 3450 को रोका, जिसमें भारी मात्रा में लोहे का सरिया लदा हुआ पाया गया। ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत ने बताया कि इस कार्यवाही की तैयारी सोशल मीडिया पर फैली जानकारी और पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर की गई थी। इस ट्रक के कागजात जांचने पर, असिस्टेंट कमिश्नर साकेत सुरेश ने पाया कि ट्रक का ईबे बिल फर्जी है। वह बिल रायपुर से दिल्ली का रूट दिखा रहा था, जबकि ट्रक छतरपुर लाया गया था। इसमें लगभग 50 लाख रुपये मूल्य का सरिया लदा हुआ था, और अनुमानित 6 से 8 लाख रुपये का सेल्स टैक्स चोरी का मामला सामने आया है।



हालांकि, अभी तक कोई व्यापारी सामने नहीं आया है कि यह सरिया किसका है, लेकिन एक व्यापारी नेता लगातार ट्रक को छुड़ाने के प्रयास में ट्रैफिक प्रभारी को फोन कर रहे थे। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस और सेल्स टैक्स विभाग की जांच और आगे की कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने इस तरह की कार्यवाही को भविष्य में भी जारी रखने की बात कही है, ताकि सेल्स टैक्स चोरी पर अंकुश लगाया जा सके।

जनसुनवाई में बिना कारणों के अनुपस्थित रहे 8 विभाग प्रमुखों को एसडीएम ने किया कारण बताओ नोटिस जारी

नौगांव। नौगांव एसडीएम विशा माधवानी ने मंगलवार की जनसुनवाई कार्यक्रम में विकासखंड क्षेत्र के विभाग प्रमुखों के अनुपस्थित रहने के मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। एसडीएम माधवानी ने अनुविभाग क्षेत्र के अनुपस्थित रहने वाले आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब विभागीय कार्यों में गति लाने के लिये विभाग प्रमुखों को जिम्मेदार ढंग से कार्यवाही करनी चाहिए। जिससे आमजनता को शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कुल 12 आवेदन पहुंचे। जिनमें निराकरण के लिये संबंधित विभाग को भेज दिए।



निरीक्षक महाराजपुर और नौगांव को अनुपस्थित रहने पर एसडीएम ने नोटिस जारी किए।

आठ विभागीय अधिकारियों को मिले नोटिस -

तहसील परिसर में हुई जनसुनवाई के दौरान विभाग प्रमुख उपस्थित न होने के कारण एसडीएम विशा माधवानी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए कि वह अनुपस्थित क्यों रहे। हालांकि महाराजपुर तहसीलदार अनिल तलेया लेट पहुंचे, लेकिन जनसुनवाई में पहुंचे हुए इनका नोटिस निरस्त किया गया। इसके अलावा हरपालपुर मंडी सचिव गोरेलाल आदिवासी, नौगांव मंडी सचिव ममता वर्मा, जनसंसाधन एसडीओ लता वर्मा, गढ़ीमलहरा नायब तहसीलदार रितु सिंघाई, पशु चिकित्सा अधिकारी मीनाक्षी पट्टेरिया के अलावा जल निगम डिप्टी मैनेजर, आरआई, सहकारिता

बाढ़ राहत बचाव कार्य के लिये हुई बैठक -

एसडीएम के द्वारा बाढ़ राहत बचाव कार्य के लिये विभाग के प्रमुखों की बैठक ली जिसमें आपदा प्रबंधन बरसात के दिनों में बाढ़ नाला उफान की समस्याओं से निपटने के लिए सामंजस्य स्थापित करके बाढ़ आपदा से निपटने के लिये तैयारियां करें। बारिश के दौरान डूबने वाले पुलों पर पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ और होम गार्ड के जवानों को अलर्ट रहने के लिये सूचित करें। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

ग्रामीणों के आरोप : बजट टिकाने लगाने पंचायतों में 3.77 करोड़ की लागत से बनाए गए सेविगेशन शेड

नौगांव। नौगांव जनपद पंचायत के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की मिलीभगत से 3 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक के बजट को ठिकाने लगाते हुए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सेविगेशन कचरा घर का निर्माण तो करा दिया है, लेकिन इनके निर्माण से पहले इनके उपयोग एवं क्रियाचन को लेकर कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की जिसके चलते राशि खर्च होने के बाद सेविगेशन तो बन गए लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी गंदगी फैली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ट्रेडिंग ग्राउंड पर कचरे के निपटन की व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज पर शासन ने ग्राम पंचायतों में भी इस व्यवस्था को शुरू करने की कवायद की है। नौगांव जनपद की 27 बड़ी पंचायतों में कचरे के उचित निपटन के लिए सेविगेशन शेड स्वीकृत किए गए। जिनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों में तो शेड बन कर तैयार हो गए हैं तो कुछ पंचायतों में भुगतान होने के बाद आज भी अधूरे पड़े हैं साथ ही कुछ पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। जनपद के अधिकारियों ने संबंधित पंचायतों को नोटिस भी जारी हुए लेकिन इसके बावजूद भी इन पंचायतों ने काम पूरा नहीं कराया है। ग्राम पंचायतों में बने यह सेविगेशन शेड स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, 15वें वित्त सहित शासन की मदद के तहत बनाए गए हैं। पंचायतों में बन रहे शेड सबसे कम सहानियां पंचायत में लाख 76 हजार एवं सबसे अधिक सिंगरावनकला में 13 लाख 30 हजार के बनाए गए हैं। साथ ही अलीपुरा पंचायत में 11 लाख 90 हजार, गरीौली में 10 लाख 25 हजार, मऊसहानियां में 10 लाख 25

हजार, बेदार में 11 लाख 90 हजार, दिलनियां में 5 लाख 87 हजार, मनकारी 11 लाख 90 हजार, मऊपुरा 5 लाख 87 हजार, सैला 5 लाख 84 हजार, खिरी 11 लाख 90 हजार, ऊजरा 11 लाख 90 हजार, उरुडऊ 11 लाख 90 हजार, डिगपुरा 7 लाख 50 हजार, बड़ागांव 11 लाख 90 हजार, दौरिया 11 लाख 90 हजार, नैगुवा 11 लाख 90 हजार, करारागंज 11 लाख 90 हजार, बिकौरा 5 लाख 84 हजार, सिंहपुर 11 लाख 90 हजार, टटम 10 लाख 25 हजार, खिरवा 5 लाख 84 हजार, अलीपुरा 11 लाख 90 हजार, चिखारी 11 लाख 90 हजार, ससेड 7 लाख 50 हजार, इमलिया 11 लाख 90 हजार, लुगासी 10 लाख, झंझन 13 लाख 04 हजार की लागत से सेविगेशन बन गए हैं या बनाए जा रहे हैं। जिसमें 27 पंचायतों में 3 करोड़ 77 लाख 91 हजार राशि खर्च होने के बाद भी शासन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, जिसके चलते गांव में जगह जगह पर गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं, गांव में सेविगेशन होने के बावजूद जनपद एवं जिला के अधिकारी इसका उपयोग शुरू नहीं करा पा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ बनाने की मुहिम पूरी नहीं हो रही है और पंचायतें गंदगी से परटी पड़ी हैं।

सेविगेशन शेड का निर्माण किया गया है। सेविगेशन निर्माण के बाद से आज तक स्थिति जस की तस है गांव में गंदगी फैली है, हां सेविगेशन शेड में कचरा प्रबंधन का कार्य न होकर आवारा पशुओं के लिए ठिकाना जरूर हो गया है।

केस 2 -

ग्राम पंचायत गरीौली में स्टीमेंट के अनुसार नहीं हुआ निर्माण, अधूरा छोड़कर कट दिया भुगतान-

गरीौली में 10 लाख 25 हजार की राशि से सेविगेशन शेड बनाया गया है। पंचायत के सरपंच एवं सचिव ने अधिकारियों की मिलीभगत से सेविगेशन शेड में स्टीमेंट अनुसार कार्य न कर अपनी मनमर्जी से कार्य को पूरा दिखा दिया, जबकि मौके पर सेविगेशन शेड में जमीन पर ने तो प्लास्टर हुआ है, न ही मानक अनुसार जाली लगाई गई और न ही दरवाजे लगाए गए इसके बावजूद पंचायत ने अधूरे कार्य को पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया।

केस 3 -

ग्राम पंचायत में लुगासी पंचायत में अमी चल रहा कार्य -

लुगासी पंचायत के खरवावा गांव में 10 लाख रूपए की राशि खर्च करके सेविगेशन शेड का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण कार्य शुरू हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो जाने के बावजूद भी कार्य पूरा नहीं हो सका।

कचरे को अलग कर नष्ट करने व खाद बनाने की योजना -

47 ग्राम पंचायतों में जो सेविगेशन शेड बनाए जा रहे हैं, उनमें कचरा एकत्रित करने के बाद गीले कचरे सूखे कचरे को अलग-अलग किए जाने की योजना है। इसको अभी तो अलग-अलग करके निस्तारित किया जाएगा, लेकिन भविष्य में गीले कचरे से खाद बनाकर उससे आय अर्जित की जा सकती है। सूखे कचरे का निपटन करने की योजना योजना के तहत इससे ईट बनाकर उससे भी ग्राम पंचायत राशि अर्जित कर सकती है।

इनका कहना है -

पंचायतों में बने सेविगेशन शेड में कचरा प्रबंधन के लिए शासन से कोई राशि नहीं है, इसलिए शासन के निर्देश पर स्व सहायता समूह को जोड़कर सेविगेशन में कचरा छोटकर खाद बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे स्व सहायता समूह को रोजगार मिलेगा और पंचायत की आमदनी में भी वृद्धि होगी।

प्रवीण तिवारी प्रभारी स्वच्छ भारत मिशन, जनपद पंचायत नौगांव

